Email: uttaranchaldeep@gmail.com
Web: www.dainikuttaranchaldeep.com

सांध्य दैनिक
उत्तरांचल दीप

● हल्द्वानी ● रविवार ● 18 फरवरी 2018

नजूल नीति से भड़की भाजपा में 'ज्वाला'

वैंडिंग जोन के लिए भी अलग सुर

ऐसा नहीं है कि भाजपा के जनप्रतिनिधि किसी एक मामले में ही अलग राय रखते हों। दिक्कत ये है कि यहां पर संगठन की ओर से किसी मुद्दे पर लाइन ऑफ एक्शन तय नहीं किया जाता है। पार्टी नेता अपने नफा नुकसान के हिसाब से मुद्दे तय कर लेते हैं। अब वैंडिंग जोन के मुद्दे को ही देखें तो यहां भी जनप्रतिनिधियों की राय अलग-अलग है। क्षेत्रीय विधायक ने किच्छा बाईपास पर मोदी मैदान के हिस्से में वैंडिंग जोन बनवाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाया है तो मेयर ने इसको अव्यवहारिक बता दिया है। मेयर का तर्क है कि शहर से बाहर होने के कारण ठेली-फड़ वालों से सामान खरीदने कौन जाएगा। मेयर इस मैदान को सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग करने के पक्ष में हैं।

नजूल भूमि को लेकर संघर्ष की शुरुआत सबसे पहले किच्छा विधायक राजेश शुक्ला ने की थी। उन्होंने 15 साल पहले नजूल भूमि पर रहने वालों को मालिकाना हक दिलाने को मशाल जुलूस निकाला था। अब सांसद भगत सिंह कोश्यारी व भाजपा जिलाध्यक्ष शिव अरोरा की पहल पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नजूल नीति को मंजूरी दी है। इसके लिए शहर की जनता उनकी आभारी है।

नत्थू लाल गुप्ता, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष

नजूल पर किसके क्या दावे

पिछले छह साल से मैं विधानसभा में नजूल को लेकर लड़ाई लड़ रहा हूं। कम से कम सौ बार मैंने विधानसभा में ये मामला उठाया। नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए भी मैंने इस मामले में कई बार सरकार को पत्र लिखे। कांग्रेस सरकार ने तो मेरी मांग पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन भाजपा सरकार ने मेरी मांग पर कार्यवाही कर नजूल नीति को मंजूरी दी है।

- राजकुमार ठुकराल, क्षेत्रीय विधायक

30 जनवरी को काशीपुर में मैंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात के दौरान नजूल नीति के मामले को पुरजोर ढंग से उठाया था। तब मुख्यमंत्री जी ने 15 दिन के भीतर कार्यवाही का भरोसा दिलाया था। ठीक 15 दिन बाद कैबिनेट ने नजूल नीति को मंजूरी दे दी है। इस तरह मुख्यमंत्री जी ने मुझसे किया अपना वायदा निभाया।

शिव अरोरा, भाजपा जिलाध्यक्ष

रुद्रपुर
अभिषेक आनंद

निकाय चुनाव से ऐन पहले शहर में कई गुटों में बंटी भाजपा में एक और द्वंद शुरू हो गया है। सरकार की नई नजूल नीति ने सभी धड़ों के बीच धधक रही 'ज्वाला' को और भी भड़का दिया है। इन गुटों के क्षत्रप नेता खुद को नजूल नीति का श्रेय देते हुए नहीं थक रहे हैं। जगह-जगह अपने समर्थकों से खुद का स्वागत कराकर वाहवाही लूटने की कोशिश हो रही है। शायद यही कारण है कि सरकार के इतने बड़े निर्णय के बाद भी संगठन की ओर से अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं हो सका है।

वर्चस्व का द्वंद

- **गुटों में बंटे भाजपाइयों में श्रेय लेने की मची होड़**
- **निगम चुनाव में सरकार के 'बूस्टर' पर संगठन ने साधा मौन**

रुद्रपुर में भाजपा में गुटबाजी कोई नई समस्या नहीं है। पिछले करीब दो दशक से पार्टी गुटों में बंटकर काम रही है। ये बात अलग है कि पिछले चार-पांच साल से भाजपाई एक-दूसरे को सरेआम गाली देने से भी नहीं चूक रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले एक विधायक का जिलाध्यक्ष को अपशब्द कहते हुए वीडियो वायरल हो चुका है। इसमें साफतौर पर दिख चुका है कि पार्टी में गुटबाजी किस स्तर पर है। निकाय चुनाव से ऐन वक्त पहले राज्य सरकार ने 14 फरवरी को नजूल नीति को मंजूरी दी। रुद्रपुर में नजूल का मामला तकरीबन हर परिवार से जुड़ा हुआ है। सरकार के इस फैसले से तकरीबन 15 हजार परिवारों को उस जमीन का मालिकाना हक मिलेगा जिस पर वे दशकों से रह रहे हैं, लेकिन अतिक्रमणकारी कहलाते थे। इस लिहाज से निगम चुनाव से पहले भाजपा के लिए शहर में ये एक बड़ा 'बूस्टअप' है, लेकिन भाजपाइयों को संगठन नहीं बस अपनी चिंता है। तभी तो सरकार के इस 'बूस्टर' का लाभ लेने को अभी तक संगठन कोई पहल ही नहीं कर सका है। हां, इतना जरूर है कि पार्टी के सरमायेदार खुद श्रेय लेने के लिए काम कर रहे हैं। दावे तो ऐसे हो रहे हैं जैसे इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए संगठन ने कोई फीडबैक ही नहीं दिया। लगातार बयान जारी कर खुद श्रेय लेने की राजनीति की जा रही है। इसमें न तो जनप्रतिनिधि और न ही संगठन के लोग पीछे हैं।

एनओसी न देने पर नपेंगे अफसर

रुद्रपुर
उत्तरांचल दीप ब्यूरो

जिला विकास प्राधिकरण एवं रेरा का मुख्य उद्देश्य निष्पक्षता व पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए नागरिकों को सस्ते व किफायती दरों पर आसानी से आवास उपलब्ध कराना तथा शहरों का सुनियोजित एवं चहुंमुखी विकास करना है। यह बात जिलाधिकारी डॉ. नीरज खैरवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना तथा रेरा के संबंध में बिल्डर्स के साथ जिला कार्यालय सभागार में आयाजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

हिदायत

- **बिल्डर्स के साथ बैठक में डीएम ने गिनाईं रेरा व विकास प्राधिकरण की प्राथमिकताएं**
- **कहा, दो नहीं एक प्लान पर ही काम करें, दिक्कत हो तो मुझे बताएं**

जिलाधिकारी ने बिल्डर्स को हिदायत देते हुए कहा कि वे दो प्लान के अंतर्गत कार्य न करें तथा यदि प्लान को पास कराने में किसी प्रकार की दिक्कत है या कोई अनावश्यक परेशान करता है तो इसकी तत्काल सूचना दें। जिलाधिकारी ने कहा कि जमीनी स्तर पर यदि नियमावली का कोई नियम सुसंगत नहीं है या किसी भी प्रकार की व्यावहारिक दिक्कत है तो उसकी लिखित में सूचना दें, ताकि समाधान किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि बिल्डर्स द्वारा बताई गयी समस्या व दिये गये सुझावों पर गहनता से विचार करते हुए कार्यवाही की जायेगी। बैठक में कुछ बिल्डरों द्वारा एनओसी समय से प्राप्त न होने की शिकायत की गई जिस पर जिलाधिकारी ने तुरंत कार्यवाही करते हुए सेवा के अधिकार के अंतर्गत निर्धारित समयावधि में एनओसी प्राप्त न होने पर एनओसी में संबंधित विभाग की सहमति मानते हुए कार्य करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने निर्धारित समयानुसार एनओसी न देने वाले विभागों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश अपर जिलाधिकारी-वित्त एवं राजस्व को दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला विकास प्राधिकरण तथा रेरा की वेबसाइट को आपस में लिंक करने हेतु शासन स्तर पर वार्ता की जा रही है।

जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनाने हेतु इच्छुक बिल्डरों की जानकारी ली तथा बिल्डर्स को बिना किसी परेशानी के नियमानुसार कार्य करने हेतु प्रेरित किया। जिलाधिकारी ने सभी बिल्डर्स व आर्किटेक्ट से सुझाव आमंत्रित किये व विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में टाउन प्लानर एसएम श्रीवास्तव ने बताया कि चल रहे प्रोजेक्टों को नियामक प्राधिकारी रेरा कार्यालय में 28 फरवरी तक निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 28 फरवरी के पश्चात 31 मार्च तक चल रहे प्रोजेक्ट का पंजीकरण कराने पर परियोजना की अनुमानित लागत का एक प्रतिशत व एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक कराने पर परियोजना लागत का दो प्रतिशत, एक मई से 31 मई तक परियोजना लागत का पांच प्रतिशत तथा एक जून के उपरांत परियोजना लागत की 10 प्रतिशत धनराशि वसूल की जायेगी।

बैठक में एडीएम प्रताप सिंह शाह, यूडीए के सहायक अभियंता आनंद राम, कॉलोनाइजर पूरन जोशी, संदीप यादव, हरीश कुमार, मनोज पांडेय, फरहान खान सहित अन्य कॉलोनाइजर उपस्थित थे।

अवैध खनन में तीन डंपर समेत सात वाहन पकड़े

हल्द्वानी। वन विभाग की टीम ने अवैध खनन में लिप्त तीन डंपर समेत सात वाहन पकड़े हैं। इन सभी वाहनों को सीज कर दिया गया है। तराई पूर्वी वन प्रभाग के गौला रेंजर गणेश त्रिपाठी ने बताया कि टीम ने गोरापड़ाव में बिना रॉयल्टी उपखनिज ले जा रहे दो डंपर पकड़े। साथ ही लालकुआं रावत नगर में अवैध खनन में लिप्त ट्रैक्टर ट्राली पकड़ी गई। टीम ने इंदिरा नगर गेट से एक पिकअप व एक डंपर तथा टनकपुर रोड गेट से एक अन्य पिकअप भी अवैध खनन में पकड़ी। रेंजर ने बताया कि इसके बाद बिंदुखत्ता से एक और ट्रैक्टर ट्राली अवैध खनन में पकड़ी गई। टीम में किशोर कुमार धपोला, धन सिंह अधिकारी, सुशील कुमार, धर्मानंद पाठक, सुनील कुमार गैरोला आदि शामिल थे।

राज्य कर्मियों को केंद्र की भांति दिये जाए वेतन-भत्ते

हल्द्वानी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में हल्द्वानी को बी श्रेणी घोषित किये जाने, वेतन भत्ते केंद्र की भांति दिये जाने, राजकीय कर्मचारियों को कैशलेश चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने जैसी मांगें उठाई गईं। इस दौरान निर्णय लिया गया कि परिषद का जल्द ही कुमाऊं स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा।

विकास खंड सभागार में आयोजित बैठक में एसीपी पूर्व की भांति 10, 16 व 26 वर्ष किये जाने, अवकाश, नगदीकरण की सुविधा देने, रिक्त पदों के सापेक्ष जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाने जैसे मुद्दे उठाये गये। इस बीच परिषद पदाधिकारियों ने बताया कि शीघ्र ही कुमाऊं स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। इसके लिए मंडल पदाधिकारियों की बैठक अल्मोड़ा में आयोजित की जाएगी। बैठक में परिषद अध्यक्ष चंद्रशेखर सनवाल, वीके शर्मा, केएल सामंत, मो.तनवीर असगर, भूपेंद्र कुमार, शशिवर्द्धन, नीता दीक्षित, नवीन जोशी, सुधीर पांडे आदि मौजूद थे।

गुरू मां
GURU MAA ENTERPRISES
हल्द्वानी-चर्च कम्पाउंड नैनीताल रोड, 9760021196
रुद्रपुर-काशीपुर बाईपास रोड,रुद्रपुर Mob: 7417550005, 9927396666